(2) पटसन माल की कुछ मदों का निर्यात विदेशी बाजारों में अधिक प्रतियोगी तथा विनिर्माताओं के लिए अधिक लाभकारी बना दिया गया है ।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों की पटसन माल के निर्यात के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

(4) नये अन्तिम प्रयोगों को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को घटाने के लिए गवेष ।और विकास प्रयत्नों के लिए उदारतापूर्वक सहायता दी जा रही है ।

(5) पटसन उद्योग के लिए गठित विकास परिषद् के माध्यम से गवेषणा एवं विकास कार्यों लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए निर्माताओं पर उपकर लगाया गया है ।

EMBEZZLEMENT FRAUD AND MISAPPROPRIATION OF MORE THAN 5 LAKHS IN NATIONALISED BANKS

6363. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will th Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to State :

(a) the details of embezzlement, fraud and misappropriation of more than 5 lakhs in the nationalised banks in the last three years and what action has been taken in each case ; and

(b) what steps Government propose to take to check embezzlement etc. ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). information to the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House.

सिलेसिलाये सूती कपड़े के निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता

6364. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये सूती कपड़ों के निर्यातकर्त्ताओं को नकद प्रोत्साहन के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नकद प्रोत्साहन के भुगतान की शर्तों के नियम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). सरकार सूती परिधानों के निर्यातकों को किसी प्रकार का नकद प्रोत्साहन नहीं देती है । तथापि सूती परिधान निर्यातकों को वस्त्र उद्योग द्वारा चलाई जा रही नकद सहायता योजना के अधीन सहायता मिलती है जिसे आगे सरकार द्वारा सहायता दी जाती है ।

सहकारी समितियों द्वारा गरीब बुनकरों का शोषण

6365. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा उद्योग मे सहकारी समितियो द्वारा किये जाने वाले गरीब बुनकरों के शोषण को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) सरकार की नीति हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की है ताकि सदस्यों को पूर्ण लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके ।

राज्य सरकारें, जो हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों की कायम करने के लिये तथा उन्हें पंजीकृत करने के लिये तथा उनके समुचित कार्यकरण के लिये जिम्मेदार हैं, बुनकर सदस्यों का शोषण रोकने के लिये